SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, it is nobody's case that all is well with the electoral system. I start it by saying that we need to purify the electoral processes and rid the system of the influence of unaccounted wealth which is a reality. But it is equally true that having been seized of this matter for a while the Election Commission, in exercise of its disciplinary power, under Article 324 has taken initiatives. These initiatives may not be fully adequate or may not be fully sufficient. But the fear in the mind of the candidate that Election observers chasing them in the Lok Sabha elections is certainly there. To that extent, the brazen use or the open use of the excessive wealth has certainly come down to an extent. It is not my case, however, that we can rest with our laurels. We need to move ahead. We need to find the law that would be credible and effective and would certainly ensure, over a period of time, the elimination of black money.

*284. The questioner (Shri N.K. Singh) was absent.

Financial assistance to Bihar for dams

*284. SHRI N.K. SINGH: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government proposes to extend financial assistance to Bihar for the construction of dams' inundation canals on flood prone rivers;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government proposes to undertake negotiations with Nepal for arriving at an effective solution for the problem of flooding in the State; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI HARISH RAWAT): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No such proposal for construction of dams' inundation canals in the State of Bihar has been received by the Government.

(c) and d) Yes, Sir. The Government of India has been having continuous dialogue and negotiations with the Government of Nepal through various bilateral mechanisms on matters related to flooding in the State of Bihar. An Indo-Nepal Joint Ministerial Commission on Water Resources (JMCWR) has been set up by both the countries which is headed by Ministers of Water Resources. The first

meeting of JMCWR was held on 15th February, 2012 wherein various issues related to water resources Sector including construction of large storage reservoirs, like Sapta Kosi and Pancheshwar Multi Purpose Project *etc* and flood management issues of Bihar were discussed. Besides, flood related issues of Bihar are also discussed in the meetings of Indo-Nepal Joint committee on Water Resources (JCWR) which has so far met 7 times and is last meeting was held 24-25 January, 2013 at Kahthmandu.

In addition to above, there are 8 other Task specific Indo-Nepal Joint Committees which also meet regularly and discuss various issues related to flood management in the States bordering Nepal including the State of Bihar.

Both the countries have already agreed for strengthening of the embankments of Bagmati, Kamla, Lalbakeya and Khando rivers and to extend the embankments along these rivers to higher ground in Nepal in order to control spilling of flood water of these rivers. Besides, the flood protection works on Gandak and Kosi projects in Nepal are already being maintained by Indian side. The bilateral Committees also meet regularly to address the issues about implementation of these works.

MR. CHAIRMAN: Questioner is not present. Let the answer be given.

श्री राजीव प्रताप रूडी: सर, इस प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ा जाए। बिहार के संदर्भ में जो उत्तर प्राप्त हुआ है, वह डैम्स के कंस्ट्रक्शन और नदियों पर बांध बनाए जाने के संबंध में है। मैं माननीया मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इस सवाल का जो जवाब आया है, उसमें इन्होंने उत्तर दिया है कि डैम के निर्माण के बारे में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इन्होंने कहा है, 'No such proposal for construction of dams' inundation canals in the State of Bihar has been received by the Government.' सर, यह सवाल ही कुछ और है। इसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि बिहार ने वहां प्रस्ताव भेजा है। आप अपने उत्तर के अंतिम पैराग्राफ को पढ़ें, जिसमें आपने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि 'Both the countries have already agreed for strengthening of the embankments of Bagmati, Kamla, Lalbakeya and Khando rivers and to extend the embankments along these rivers to higher ground in Nepal in order to control spilling of flood water of these rivers." सर, इसका मतलब क्या हुआ? यह भारत और नेपाल के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसमें या तो भारत की सरकार के द्वारा भारत की योजना के तहत पैसे दिए जाने हैं या नेपाल की सरकार के द्वारा नेपाल की योजना के तहत पैसे दिए जाने हैं, फिर इसमें बिहार सरकार की भूमिका क्या है? यह दो देशों के बीच का समझौता है, तो उस समझौते के तहत बिहार सरकार प्रस्ताव बनाकर थोड़े ही भेजेगी? यह तो केन्द्र

सरकार को तय करना है कि आप दो देशों के बीच में कौन-कौन से समझौते करते हैं, उस समझौते के बाद किस देश को कितना पैसा देते हैं और उसके बाद निर्माण होता है। सर, इस प्रश्न का उत्तर जिसने भी बनाया है, इसमें सरकार ने पूरी तौर से बिहार को गुमराह किया है, देश को गुमराह किया है और सदन को गुमराह किया है। कृपया इसका स्पष्टीकरण दें कि जब दो देशों के बीच कोई समझौता होता है, तो क्या राज्य सरकारें उस प्रस्ताव को बना कर केन्द्र सरकार को देती है और केन्द्र सरकार उन प्रस्तावों को स्वीकृति देकर दो देशों के बीच में समझौते को लागू करती है?

MR. CHAIRMAN: Please, put your question.

श्री राजीव प्रताप रूडी: सर, इससे स्पष्ट प्रश्न और क्या हो सकता है। यह उत्तर बिल्कुल गलत है। बिहार प्रस्ताव क्या बनाकर देगी, जब केन्द्र सरकार को यह तय करना है कि इस योजना के लिए दो देशों के बीच में पैसा दिया जाए। यह गलत उत्तर क्यों दिया गया है और इस प्रकार से सदन को और बिहार को गुमराह करने का क्यों प्रयास किया गया और इसका सही उत्तर क्या होगा, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

श्री हरीश रावत: महोदय, मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वह प्रश्नकर्ता के प्रश्न के पार्ट - a और पार्ट - b को देखें, जिसमें उन्होंने सवाल किया है, "(a) whether Government proposes to extend financial assistance to Bihar for the construction of dams' inundation canals on flood prone rivers;". सर, मैंने इस पार्ट का जितना मेरी समझ से उत्तर बनता था, वही उत्तर देने की कोशिश की है, क्योंकि मुझसे सवाल पूछा गया है कि dams' inundation canals बनाने का प्रस्ताव है? मैंने इसके उत्तर में यह कहा है कि ऐसा कोई प्रपोज़ल बिहार गवर्नमेंट से हमको प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: सर, यही तो सवाल है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please, let him finish. Everybody listened to you in rapt silence. Please, listen to him. ...*(Interruptions)*...

श्री राजीव प्रताप रूडी: सर, ...**(व्यवधान)**...

श्री हरीश रावत: सर, मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करता हूं कि जरा प्रश्न के पार्ट-a और पार्ट-b को वे और गौर से पढ़ लें, उसमें साफ तौर से मुझसे पूछा गया है कि dams' inundation canals बनाने का प्रस्ताव है। मैंने यह कहा है कि ऐसा प्रस्ताव हमें बिहार गवर्नमेंट से प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि राज्य सरकारों से जो प्रस्ताव प्राप्त होते हैं ...**(व्यवधान)**... रूडी साहब, यदि मुझसे यह पूछा गया होता कि बिहार में फ्लड प्रोटक्शन के कामों के लिए क्या-क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, तो मैं आपको उसके अनुरूप उत्तर देता। यदि आप पूछना चाहते हैं तो पूछें मुझसे। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Will you please stop arguing?

श्री हरीश रावत: मुझसे पूछा गया है ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Look, if you are not satisfied with the answer, please, give in writing that you have got a misleading answer. ...*(Interruptions)*... We can go on with the next question.

श्री हरीश रावत: महोदय, मैं आपका प्रोटक्शन चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please, just one minute Mr. Rudy, you are taking up precious time. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: But, he has not read his own question. His answer is ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: If you are not satisfied with the answer, please give a written representation.

श्री राजीव प्रताप रूडी: यह उत्तर बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please, don't take up precious time. There are other questions to be taken up.

श्री राजीव प्रताप रूडी: जिस प्रकार से केन्द्र की सरकार ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please, ...*(Interruptions)*... Look, you have taken five minutes. I am afraid, I cannot allow this.

श्री राजीव प्रताप रूडी: *

MR. CHAIRMAN: I will go straight to the next question if you don't sit down.

श्री राजीव प्रताप रूडी: *

MR. CHAIRMAN: Mr. Rudy, please.

श्री राजीव प्रताप रूडी: *

MR. CHAIRMAN: If you wish to hear your own voice, you are welcome to it.

श्री राजीव प्रताप रूडी: *

MR. CHAIRMAN: आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हैं तो लिखित में उत्तर दीजिए।

---

*Not recorded.

श्री राजीव प्रताप रूडी: *

MR. CHAIRMAN: This is very ...*(Interruptions)*...

श्री राजीव प्रताप रूडी: *

MR. CHAIRMAN: None of this is going on record. Shri Shivanand Tiwari.

श्री शिवानन्द तिवारी: शुक्रिया, जनाब। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कबूल किया है कि ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: हमको भी मौका दीजिए।

श्री सभापति: आने दीजिए, I can take only one question at a time. Why are we displaying this amazing impatience?

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कबूल किया है कि बिहार में बाढ़ एक समस्या है। उस समस्या के समाधान के लिए वाटर मैनेजमेंट करने के लिए 9 समितियां हिन्दुस्तान और नेपाल के बीच में बनाई गई हैं। एक नई समिति अभी हाल में बनी है, जिसकी 15 फरवरी, 2012 को बैठक हुई। सभापति महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 66 वर्षों के बाद भी आज तक भारत सरकार और नेपाल के बीच में इस तरह का कोई समझौता नहीं हुआ, जिससे बिहार को और उत्तर प्रदेश को बाढ़ से मुक्ति मिल सके। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने कोई आकलन किया है कि 10 वर्षों के दरम्यान बिहार में जो फसलों का नुकसान हुआ है, कृषि फसलों का नुकसान हुआ है तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान होता है, वह कितना नुकसान होता है और उस नुकसान की भरपाई आप कितना करते हैं? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री हरीश रावत: सर, माननीय तिवारी जी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और यह लगातार हमारी भी चिंता रही है। इसीलिए सतत इस बात की कोशिश करनी होती रही है और हम नेपाल के साथ द्विसम्बन्धीय संधियों के द्वारा नेपाल से बाढ़ नियंत्रण के लिए, वहां पर मल्टी-परपज डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाने, एम्बैंकमेंट्स बनाए जाने के सवाल पर बातचीत कर रहे हैं। जैसाकि खुद माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, उसके लिए मंत्रिस्तरीय समिति स्थापित की गयी है जिसकी एक बैठक हो चुकी है। सर, उसके फॉलो-अप में सेक्रेटरी लेवल की बैठक भी हुई थी। इसके अलावा हमारी अलग-अलग टास्क-स्पैसिफिक कमेटीज की भी बैठक हुई है, जैसाकि उन्होंने खुद कहा है कि 9 ऐसी बैठकें हो चुकी हैं। सर, 9 नहीं बल्कि ऐसी 7 बैठकें हुई हैं और अगर मंत्रिस्तरीय भी लगा लें तो 8 बैठकें हुई हैं। सर, मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद बागमती, कमला, लालबेख्या और खांडू रिवर के ऊपर भी एम्बैंकमेंट्स बनाने के प्रस्ताव पर अब अग्रिम रूप से टैक्निकल कमेटीज काम कर रही हैं, ताकि वहां से बाढ़ का जो पानी बिहार में आ जाता है, उसको वहीं कंट्रोल किया जा सके, उसको वहीं प्रॉपर्ली चैनलाइज किया जा सके। उसके अलावा, गंडक और कोसी प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी भारत सरकार एमईए

*Not recorded.

के माध्यम से जो पैसा प्राप्त होता है, उसके तहत एम्बैंकमेंट्स बनाने का काम कर रही है। उससे नेपाल गवर्नमेंट काफी संतुष्ट है और मैंने नेपाल के वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर से खुद बातचीत की थी। वह खुद चाहते हैं कि इस प्रोसेस को खुद एक्सपैडाइट किया जाए।

अब आपने जानना चाहा कि कितना नुकसान हुआ है, अभी तक बिहार बाढ़ के रूप में हर साल करीब 242.71 करोड़ का नुकसान उठा रहा है। इस तरह कुल मिलाकर बिहार ने 13,655 करोड़ रुपए के करीब नुकसान उठाया है। सर, यह देश की एक बहुमूल्य सम्पदा है और बिहार में प्रति वर्ष बाढ़ से इस तरीके का नुकसान होता है, इसलिए हमने 11वीं पंचवर्षीय योजना में करीब 689.93 करोड़ रुपए एफएमपी यानी फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत दिए हैं। उसके जरिए वहां 40 प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी बिहार से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, भारत सरकार उन पर उदारतापूर्वक विचार करेगी।

श्री प्रेम चन्द गुप्ता: सर, नेपाल से आनेवाली नदियां हर साल बिहार के ऊपरी हिस्से में जो तबाही करती हैं, सारा देश इस बात को जानता है। आपने बताया कि हर साल 242 करोड़ का नुकसान बाढ़ से बिहार को होता है, यह 200-250 करोड़ कुछ नहीं है, मान्यवर, इससे कई गुना नुकसान होता है, लाखों हैक्टेयर जमीन बर्बाद हो जाती है।

श्री सभापति: प्रश्न काल का समय खत्म हो रहा है, जल्दी से प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री प्रेम चन्द गुप्ता: मान्यवर, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि कोसी के ऊपर बांध बनाने या एम्बैंकमेंट स्ट्रांग करने का कोई प्रपोजल बिहार सरकार की तरफ से नहीं आया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि अगर ऐसा कोई प्रपोजल आता है तो क्या केन्द्र सरकार उसे कंसिडर करेगी? दूसरे, अगर बिहार सरकार इस इश्यू का इनीशिएट नहीं करती है, तो क्या ह्यूमैनेटेरियन ग्राउंड पर आप काम शुरू करेंगे?

श्री हरीश रावत: सर, मूल प्रश्न के पार्ट "ए" व "बी" को पहले प्रश्नकर्ता और माननीय प्रेम चन्द गुप्ता जी द्वारा गलत समझा गया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रेम चन्द गुप्ता: आप पहल करेंगे?

श्री हरीश रावत: मैं उस पर भी आ रहा हूं। इसलिए यह कहना कि बिहार सरकार ने प्रपोजल नहीं भेजे हैं, गलत होगा। मैं इस इम्प्रेशन को दूर करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार बराबर प्रपोजल्स भेज रही है और भारत सरकार भी, जैसे-जैसे प्रपोजल्स प्राप्त हो रहे हैं, उन पर विचार कर रही है। इस समय सप्तकोसी प्रपोजल पर हम ऑलरेडी नेपाल सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं और दूसरे भी जो बाढ़ प्रोटेक्शन के प्रपोजल्स हैं, उन पर भी नेपाल सरकार से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा इंटर-स्टेट लिंकिंग के प्रोजेक्ट्स पर भी बिहार सरकार और हमारे बीच में बातचीत चल रही है।

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.